Growth Rate for Exports

4315. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have reiterated the need for 20 per cent growth rate for exports;

(b) if so, what strategy is being adopted to achieve these export targets during 1998-99;

(c) what has been the state of our exports during the last three years *i.e.* targets fixed and targets achieved and whether there was any short-fall; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes Sir.

(b) The Government has initiated a number of policy initiatives to achieve this target. The external trade sector of India has been further liberalised with the changes introduced in the new Exim Policy. The existing export incentive schemes have been strengthened while an effort is being made to evolve new strategies for accelerated growth of exports. Procedures are constantly being simplified and sector-specific issues are beign addressed vigorously to deal with sectoral constraints. Efforts are also being made to diversify the export basket as well as to focus on the directional thrust.

(c) and(d) Details regarding targets fixed and growth achieved during the last three years are given below:

Targets (in dollar terms)

	1995-96	1996-97	1997-98
Fixed	17%	20%	18%
Achieved	1.4%	4.01%	2.64%

Export Potential of Minerals

4316. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether MMTC has done any survey of the export of minerals from Cuddapah district in Andhra Pradesh;

(b) if so, whether there is any potential for enhancing mineral exports from Cuddapah;

(c) what steps are proposed to be taken in this regard by MMTC; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) In order to increase exports, MMTC has made a study of the availability of minerals in different parts of the country including Barytes exploited in Cuddapah distt. in Andhra Pradesh.

(c) and (d) Exports of Barytes is permitted under Open General Licence (OGL). The main source of barytes are the mines of Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC) located in Cuddapah distt. MMTC's marketing efforts included participation in a tender floated by APMDC for sale of barytes but were not successful.

गुलाबों का निर्यात

4317. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से गुलाब के फूल प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं तथा इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में पुष्कर और इसके आसपास के क्षेत्रों में गुलाब के फूलों की खेती होती है तथा वहां से इनका निर्यात किया जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा गुलाब के फूलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सहयोग दिया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) मात्रात्मक रूप में फूलों के निर्यात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गत वर्षों के दौरान मूल्य युक्त अथवा कलम रहित गुलाबों का निर्यात निम्नानुसार रहा है?

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1995-96	1.29
1996-97	0.88
1997-98	0.32

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

निर्यातों के राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) गुलाब जैसे पुष्पोत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं —

(I) श्रेणीवार/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों गुणवत्ता परीक्षण उपकरण की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(II) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(III) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(IV) क्रेता-विक्रेता बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय मेलों, पुष्प प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों में सहभागिता करने जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(V) पुष्पोत्पाद और बागवानी उत्पादों जैसी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागारों की सुविधाओं की स्थापना करना/हाल ही में ऐसी सुविधा इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन, नई दिल्ली पद शुरू की गयी है;

(VI) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन आदि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी सलाहकार सेवाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना।

Import of Wheat

4318. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of wheat imported during the current financial year, till date;

(b) the expenditure incurred on this so far;

(c) the names of the countries from where the wheat has been imported;

(d) the total quantity of wheat demanded by States including Tripura and Gujarat for their monthly PDS; and

(e) whether it is a fact that there is acute shortage of wheat in the country?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) to (c) STC contracted for purchase of 15 lakh tonnes of wheat on Government account from Australia on FOB basis @ US $ 142.50 per tonne during 1998-99.

(d) The Deptt. of Food & Civil Supplies have intimated that under Targeted Public Distribution System which was launched from June, 1997, the monthly quota of wheat and rice to all States/UTs (Union Territories) has been fixed, so as to provide foodgrains to the population living below the poverty line @ 10 Kg. per family per month at specially subsidised rates. The Deptt. of Food & Civil Supplies have also intimated that Transitory allocation of foodgrains for population above the poverty line is also being made which has been fixed on the basis of past lifting of foodgrains in States/UTs.

(e) No, Sir. The Deptt. of Food & Civil Supplies have intimated that the production of wheat in 1997-98 is estimated at 66.38 million tonnes as against 69.27 million tonnes in 1996-97 and 62.10 million tonnes in 1995-96. Moreover, the stock of wheat in the Central Pool as on 1st July, 1998 is 164.76 lakh tonnes against a buffer form of 131 lakh tonnes.

औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारी

4319. श्री बलबन्त सिंह रामूवालिया:
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के अधीन औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या लगभग 21 लाख है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का वास्तविक अनुमान क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होने के संबंध में कोई अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो अधिशेष कर्मचारियों की संख्या के संबंध में क्या अनुमान है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) 31-3-1997 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 20.2 लाख है।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी उपक्रमों में अधिशेष कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। सरकारी उपक्रमों में अधिशेष कर्मचारियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

Impact of reduction in import tariff on domestic industry

4320. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the negative impact of the steep reduction in import tariff on project imports and finished products on the domestic industry;